LOK SABHA

Tuesday, November 14, 1967/ Kartika 23, 1889 (Saka)

The LOK SABHA met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

WAGE BOARD FOR JOURNALISTS

*

*31. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI:
SHRI S. M. BANERJEE:
SHRI CHENGALRAYA NAIDU:
SHRI DEVEN SEN:
SHRI S. KUNDU:

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Wage Boards for Working Journalists and non-journalists have submitted their reports;

(b) if so the main recommendations made by the Boards; and

(c) the decisions taken thereon?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Government decisions on the Report of the Wage Board for Working Journalists were announced in an order issued on the 27th October, 1967. Copies of the order along with the Report have been placed in the Parliament Library.

Government decisions on the Report of the Wage Board for Non-Journalists are expected to be announced shortly along with the main recommendations of that Board.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: According to the Notification which the hon. Minister just now mentioned, the Government have accepted the recommendations of the Wage Board for Working Journalists. After four years this Board has submitted this Report. I would like to know when it is actually going to be implemented. It is to be implemented with retrospective effect. When are they going to implement it?

SHRI HATHI: Now that the recommendations have been accepted by the Government, they will have to be implemented by the employers.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: If there is any attempt from any interested quarter to delay it further, will the Minister still stand by the commitment that he has made to this House today?

SHRI HATHI: There may be attempts: one attempt may be to go to a court of law and if that is done, I do not think that Government can do much; otherwise, we have been trying with the employers to see that the Wage Board's recommendations are implemented. (*Interruption*) It is not a suggestion. The whole thing is being considered.

SHRI S. M. BANERJEE: It is quite evident from the statement of the hon. Minister that some of the newspaper employers may go to a court of law, and in that case, he has expressed his helplessness. In the past, the ex-Labour Minister, Shri Nanda, assured that if there was any such attempt by the employers in implementing any award of the Wage Board, proper legislation would be brought in the House to see that the recommendations of the Wage Board are implemented. I would like to know whether Government are contemplating to bring any such legislation in the event of failure on the part of the employers in implementing the recommendations.

SHRI HATHI: Yes, Sir. The whole question about acceptance of the recommendations of the Wage Board is under the consideration of the Government; not only this, I have also taken up the matter at the Standing Labour Committee; we have appointed a small Sub-Committee consisting of the representatives of workers and employers to find out the best solu-

tion for this and the Sub-Committee is to make the report within two months.

SHRI S. M. BANERJEE : My question has not been answered. My question was whether Government was contemplating to bring in any legislation in the event of failure on the part of the employers in implementing the recommendations.

SHRI HATHI : That is what I have said. The whole question is whether the Wage Board itself should be statutory or whether the Wage Board should remain as it is and the implementation part of it may be made statutory. The whole matter is being considered.

श्री बेचेन सेन : वेतन बोर्ड के जो फैसले होते हैं उनको मानने में सरकार द्वारा हमेशा देर की जाती है और जब उनको मान भी लिया जाता है तो उनके इम्प्लेमेंटेशन में और देर होती है । कृपा करके आप दो काम करें । एक तो इस तरह की आप व्यवस्था करें कि वेतन बोर्ड का जो फैसला हो वह कानूनी तौर पर सब पार्टीज पर लागू हो और दूसरे वेतन बोर्ड का फैसला अगर सर्वसम्मति से न भी हो, केवल बहुमत हो तो भी सरकार उसको मान ले ।

श्री हाथी : माननीय सदस्य ने दो बातें कही हैं । पहली बात तो उन्होंने यह फरमाई है कि कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे वेतन बोर्ड का फैसला इम्प्लेमेंट हो सके । मैंने अभी इसके बारे में निवेदन किया है कि हम सोच रहे हैं इसके बारे में और इसीलिए एक कमेटी बनाई है जो यह बताये कि क्या होना चाहिये ? क्या वेतन बोर्ड को स्टेचुटरी बना दिया जाए या उसके फैसलों को ऐसा बना दिया जाए कि वे बाई ला इम्प्लेमेंट हों ।

जहां तक मैजोरिटी रिकोमेंडेशन का सम्बन्ध है मैं बतलाना चाहता हूं कि जब रिकोमेंडेशंज युनैनिमस होती हैं तब तो गवर्नमेन्ट उनको मानती ही है और अगर मैजोरिटी रिकोमेंडेशन भी होती हैं तब भी गवर्नमेंट की तरफ से आम तौर पर उसको मान लिया जाता है और इधर उधर हेरफेर करना जरूरी हो तभी हेरफेर किया जाता है ।

SHRI S. KUNDU : May I know whether the hon. Minister is aware that there has been a great resentment throughout the country among the journalists, and they have said that this award is not a progressive one but a regressive one since this award has denied to some of the journalists the privileges which they were getting before, and if so, whether the hon. Minister is thinking of reconstituting another wage board which will give a fair wage to the working journalists ?

SHRI HATHI : I had a discussion with the journalists. There were representations received from the journalists to the effect that this wage board award did not satisfy their demands. On the other hand, we have also received representations from the employers to the effect that this wage board award has gone far beyond that. I had, therefore, convened a meeting of both the employers as well as the journalists. This is a statutory board, and Government have to accept their recommendations as they stand. If Government, however, want to make any change, then the changes have to be notified, and objections have to be invited. Further hearing has to be given. I put it to the journalists whether they would like to go through this procedure or they would like to accept the award as it was, and they said that it was better to accept it as it was rather than prolong it further.

SHRI A. V. PATIL : May I know whether it is a fact that the proprietors of the newspapers have already gone to a court of law ?

SHRI HATHI : I do not know exactly; I have no information. I have not received any notice or anything like that.

श्री जार्ज फरनेंडीज : जहां तक हमारी जानकारी है अखबारों के मालिकों ने और कर्मचारियों ने दोनों ने ही वेज बोर्ड की सिफारिशों के बारे में शिकायतें की हैं । उसके बाद सरकार की ओर से एक त्रिपक्षीय सम्मेलन जिस में अखबारों के मालिक, पत्रकारों के

प्रतिनिधि और सरकारी लोग हाजिर थे बुलाया था । मैं जानना चाहता हूं कि इस त्रिपक्षीय सम्मेलन को बुलाने की क्या जरूरत थी ? इस सम्मेलन में क्या बहस हुई और उसका क्या नतीजा निकला ? क्या कारण है कि आज फिर सरकार इन सिफारिशों के बारे में यहां पर बोलने लगी है ?

श्री हाथी : यह बात सही है कि त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया गया था और इसलिए बुलाया गया था कि दोनों पक्षों में जो मतभेद हैं उसको जितना दूर किया जा सके करने की कोशिश की जाए । मतभेद काफी था । एम्प्लायर्ज कहते थे कि जो वेतन दिया गया है, जो पे स्केल दिये गये हैं वे इतने ज्यादा हैं कि हम दे नहीं सकेंगे । मूल बात में ही मतभेद था । फिर उन्होंने कहा, कि हम को कुछ समय चाहिये, हम दोनों मिलेंगे अलग और कुछ फसला हो सकेगा तो हम करेंगे । पन्द्रह दिन का उन्होंने समय मांगा । पन्द्रह दिन के समय के बाद फिर दोनों ने लिखा कि आपस में कुछ समझौता नहीं हो सका है इसलिए जो वेतन बोर्ड की जो रिकोमेंडेशन्ज हैं उनको हम नहीं मानेंगे ।

श्री शिव नारायण : उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि हमने जरनलिस्टों से बात की है मालिकों से बात की है । मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कौन है, गवर्नमेंट है, मालिक हैं या जरनलिस्ट हैं । गवर्नमेंट को डिसिशन लेने में क्या आपत्ति है और कब तक वह ले लेगी ?

श्री हाथी : इस में मालिकों की बात नहीं है और न ही सत्ता की बात है । जहां तक मालिकों और कर्मचारियों के सम्बन्धों की बात होती है लेबर मिनिस्ट्री की यही इच्छा रहती है कि दोनों के बीच जहां तक हो सके संघर्ष कम हो और समझौते से काम चले । जितना एग्रीमेंट से हो सके काम कराया जाए । इसलिए वह बात हुई थी और उनको बुलाया था । लेकिन जब उनमें फैसला नहीं हो सका तब गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और इसके बारे में एनाउंसमेंट भी कर दिया ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर गया है कि छोटे नगरों में ऐसे हजारों पत्रकार हैं, जिन्हें सिवाये डाक-खर्च के कुछ नहीं मिलता है; यदि हां, तो जो कमेटी बनाई गई है, क्या वह इस तरफ ध्यान देगी कि उनकी ठीक प्रकार से व्यवस्था की जाये ? इस के अतिरिक्त बहुत से झगड़े काफ़ी दिनों तक न्यायालयों में चलते रहते हैं और जल्दी नहीं सुलझते हैं । क्या कमेटी इस बात पर विचार करेगी कि ऐसे झगड़ों को जल्द से जल्द निपटाया जाये ?

श्री हाथी : वेज बोर्ड ने इस बारे म अपना फैसला दिया है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं ने पूछा है कि जो हजारों ऐसे पत्रकार हैं, जो छोटे नगरों और गांवों में रहते हैं और जिन को डाक-खर्च के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है, क्या कमेटी उन की उचित व्यवस्था करने की तरफ ध्यान देगी ।

श्री हाथी : किस पत्रकार को कितना वेतन मिलना चाहिए, वेज बोर्ड ने इस बारे में अपना फ़ैसला दिया है ।

Space Age in Communications

*32. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India propose to join the Space Age in the field of Communications in about two years time;

(b) if so, the site of the station selected and the estimated cost thereof; and

(c) whether any technical collaboration has been envisaged ?